शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 49 अंक-13 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 18-25 मार्च 2024 मूल्य पांच रूपये

नौ लोगों के भाजपा में शामिल होने के बाद सरकार कितनी देर सुरक्षित रह पायेगी?

जिस अध्यक्षा को संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया उससे चुनाव लड़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है

मुख्यमंत्री के साथ शिमला आने के बाद भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्थिति का संज्ञान लेने का कोई संदेश क्यों नहीं दिया?

क्या हाईकमान अब भी मुख्यमंत्री के चश्मे से ही प्रदेश को देख रहा है?

शिमला/शैल। कांग्रेस के छः बागियों और तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा त्यागपत्र देने के बाद सभी नौ लोगों के भाजपा में विधिवत रूप से शामिल होने से प्रदेश की राजनीति का अस्थिरता की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है। निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल होने के बाद स्वतः ही दल बदल कानून के दायरे में 1985 में हुये संशोधन के बाद आ जाते हैं। फिर इन विधायकों ने भाजपा में शामिल होने से पहले अपनी विधायकी से त्यागपत्र दिये हैं। उनके त्यागपत्र देने पर कहीं से कोई ऐसा आरोप नहीं है कि ऐसा करने के लिए इन पर कोई दबाव था। ऐसे किसी आरोप के बिना इनके त्यागपत्रों को तुरन्त प्रभाव से स्वीकार न करना इनको मनाने के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा में विधिवत रूप से शामिल होने के बाद कांग्रेस के छः विधायकों की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में स्वतः ही अर्थहीन हो जाती है। इसलिये इस याचिका को आने वाले दिनों में वापस ले लिया जायेगा । शैल के पाठक जानते हैं कि इस बारे में हमने बहुत पहले ही सारी स्थिति के बारे में पूरी स्पष्टता के साथ लिख दिया था। अब यह सवाल उठ रहा है कि इस सारे प्रकरण का अंतिम परिणाम क्या होगा।

अब तक जो घट चुका है उसके मुताबिक नौ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। क्या इन उपचुनावों में कांग्रेस कोई सीट जीत पायगी? कांग्रेस यह उपचुनाव और लोकसभा चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेगी? कांग्रेस अध्यक्षा सांसद प्रतिभा सिंह मण्डी से चुनाव न लड़ने की बात कह चुकी हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मानसिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है । उनके इस कथन पर कांग्रेस विधायकों द्वारा अध्यक्षा को बदलने की मांग तक सामने आ गयी। इस पर यह सवाल उठ रहा है की क्या प्रतिभा सिंह के पास कोई और विकल्प था? इस बीच आनन्द शर्मा का एक ब्यान आ गया है जिसे सीधे राहुल गांधी को ही चुनौती देना माना जा रहा है। ऐसे परिदृश्य में प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति का प्रश्निन होना माना जा रहा है क्योंकि आनन्द शर्मा प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य भी हैं।

इस वस्तुस्थिति में प्रदेश में यदि कांग्रेस की स्थिति को खंगाला जाये और अध्यक्षा की भूमिका से शुरुआत की जाये तो सबसे पहले यह सामने आता है की बतौर अध्यक्षा पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी होने का मुद्दा उन्होंने बार-बार मुख्यमंत्री से लेकर हाईकमान तक उठाया। क्या यह मुद्दा उठाना गलत था? शायद नहीं । लेकिन शिमला से लेकर दिल्ली तक उनकी बात नहीं सुनी गयी। फिर जब इस संकट के समय जब दिल्ली ने पर्यवेक्षक भेजे तो उनकी रिपोर्ट में हॉलीलॉज पर ही सारा दोष डालकर उनको हटाने की सिफारिश कर दी गयी। इस कथित रिपोर्ट को मीडिया में खूब उछाला गया। ऐसे में यह स्वभाविक सवाल उठाता है कि एक तरफ तो सारे संकट के लिये हॉलीलॉज को जिम्मेदार ठहराकर उनको हटाने की बात की जाये और इसके साथ उनसे चुनाव लड़ने की उम्मीद की जाये तो यह दोनों परस्पर विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? क्या इससे उन्हें चुनाव में हरवाने की योजना के रूप में देखा जा सकता है? इसी क्रम में यदि इस संकट को सुलझाने के प्रयासों पर नजर डालें तो यह सामने आता है की राज्यसभा में क्रॉसवोटिंग के बाद इन बागियों के खिलाफ जनाक्रोश उभारने का प्रयास किया गया। इनके क्षेत्रों में प्रदर्शनों और उनके होर्डिंग्ज को काला करने तोड़ने फोड़ने की रणनीति अपनाई गयी? लेकिन क्या सही में कहीं भी जनाक्रोश उभर पाया? जिस ढंग का यह जनाक्रोश बाहर आया उससे स्पष्ट हो गया कि यह प्रायोजित है और स्थायी नहीं बन पायेगा। आज यह कथित जनाक्रोश स्वतः ही शांत हो गया है। फिर इन बागियों के खिलाफ प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को प्रयोग करने का प्रयास किया

शेष पृष्ठ 8 पर.....

क्या भाजपा विधायक दल सामूहिक त्याग पत्र देगा?

क्या यह प्रचार अध्यक्ष के पास लंबित अवमानना याचिका वापस करवाने का प्रयास है

क्या शान्ता के साथ पार्टी के और स्वर भी उभरेंगे?

क्या भाजपा प्रदेश को मध्यावधि चुनाव की ओर ले जा रही है?

शिमला/शैल। भाजपा ने कांग्रेस के छः बागिया और तीन निर्दलीय विधायकों को उनसे विधायकी से त्यागपत्र दिलवाकर भाजपा में शामिल करवाकर प्रदेश सरकार को अस्थिरता के कगार पर पहुंचा दिया है। क्योंकि इन नौ स्थानो पर उपचुनाव होने आवश्यक हो गये हैं। भाजपा के नौ विधायकों के खिलाफ अवमानना कि याचिका अध्यक्ष के पास लंबित चल रही है। यदि यह याचिका वापस नहीं ली जाती है और उनके खिलाफ भी स्पीकर का फैसला आ जाता है तो उनकी विधायकी भी जाने की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसी बीच यह फैल गया है कि भाजपा के सभी 25 विधायक भी त्यागपत्र दे रहे हैं । इस अफवाह का भाजपा की ओर से कोई खण्डन भी नहीं आया है और ऐसा माना नहीं जा सकता कि भाजपा नेतृत्व को इसकी जानकारी ही न हो । ऐसे में यह लगता है कि इस अफवाह के पीछे कोई रणनीति काम कर रही है । पहली नजर में यह माना जा रहा है कि भाजपा विधायकों के खिलाफ लंबित चल रही यचिका को वापस लेने का इससे दबाव बनाया जा रहा है । दूसरे अर्थों में यदि यह याचिका वापस नहीं ली जाती है तो पूरे प्रदेश में विधानसभा

शेष पृष्ठ 6 पर.....

मुख्य सचिव ने हितधारकों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा की

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा आयोजित प्रशासनिक सचिवों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को उनकी सौंपी गई भूमिका को ईमानदारी से निभाने के निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक को लाइसेंसी आग्नेयास्त्रों की शत-प्रातिशत जमाबंदी और लंबित गैर जमानती वारंटों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि मतदान केंद्रों के रूप में उपयोग की जाने वाली उनकी इमारतों का अच्छी तरह से रख-रखाव किया जाए और उनमें आयोग द्वारा निर्धारित सभी सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हों।

उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा क्षेत्रों को बन्द करने और शराब और अन्य नशीले पदार्थों के अवैध उपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए। स्वास्थ्य विभाग को मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को कैशलेस इलाज सुविधा की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं की सहायता के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर व्हीलचेयर और स्वयंसेवकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नामांकन से छूटे हुए दिव्यांग मतदाताओं का मतदाता सूची में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं प्रधान सचिव निर्वाचन मनीष गर्ग ने प्रदेश में चुनाव तैयारियों के प्रति विभिन्न विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व, जल शक्ति विभाग और गृह ओंकार चंद शर्मा, प्रमुख सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव प्रशासनिक सुधार सी. पॉलरासु, सचिव शिक्षा और सूचना एवं जन संपर्क राकेश कंवर, पुलिस महानिदेशक संजीव रंजन ओझा और विभागाध्यक्ष समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

60 प्रतिशत से कम मतदान दर्ज करने वाले मतदान केन्द्रों पर मतदान बढ़ाने के लिए मिशन-414

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2019 में हिमाचल प्रदेश के 414 मतदान केंद्र ऐसे थे, जिनमें 60 प्रतिशत से कम मतदान दर्ज हुआ था, जिसके दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव-2024 के लिए इन मतदान केंद्रों में मतदान दर बढ़ाने के लिए 'मिशन-414' अभियान आरम्भ करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इन सभी मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया जाएगा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को प्रत्येक बूथ पर 'यूथ आइकॉन' बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग उन मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहा है, जहां मतदान बहिष्कार का इतिहास रहा है और ऐसे मतदान केंद्रों पर 'येस, आई विल वोट' थीम के तहत विशेष हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा, जिसे इन मतदान केन्द्रों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय बच्चों द्वारा बनाए गए निमंत्रण कार्ड भी वितरित किए जाएंगे।

श्री गर्ग ने कहा कि जन-जन से जुड़ने और उन्हें लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए साहसिक, अन्य खेल संघों आदि को भी शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए उत्सव अभियान के तहत विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, मतदाता जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे।

मौसम पूर्वानुमान एजेंसियों की भूमिका अहम

नौणी विवि में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया

शिमला/शैल। डॉ यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के पर्यावरण विज्ञान विभाग के छात्रों और शिक्षकों ने शनिवार को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया। यह कार्यक्रम मौसम विज्ञान पर चर्चा करने और मौसम, जल विज्ञान और पर्यावरण डेटा को इकठा, प्रसारित और विश्लेषण करने, और जीवन को आरामदायक बनाने के लिए मौसम की

भविष्यवाणी को संभव बनाने में शामिल लोगों की सराहना करने का एक दिवस में मनाया गया।

सभा को संबोधित करते हुए पर्यावरण विज्ञान विभाग के एचओडी डॉ. एसके भारद्वाज ने बताया कि जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक वास्तविक खतरा जिसके प्रभाव दिखाई दे रहे हैं और हमें तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है। डॉ. भारद्वाज ने कहा कि जलवायु और मौसम हमारे जीवन की हर गतिविधि को प्रभावित करते हैं और इसलिए विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई प्रारंभिक चेतावनियां जीवन बचाने में मदद करती हैं।

उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य 13 हमें जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। इस लक्ष्य में प्रगति अन्य सभी सतत विकास लक्ष्यों में प्रगति सुनिश्चित करती है। इसलिए इस दिवस की इस वर्ष की थीम को विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाकर जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए दुनिया के लिए एक चेतावनी के रूप में चुना गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कार्य जलवायु कार्रवाई के लिए अपरिहार्य है। इस संगठन की स्थापना 1873 में हुई थी।

इस अवसर पर वानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ. चमन लाल ठाकुर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने आपदाओं को रोकने के लिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के काम की सराहना की। उन्होंने बताया कि सटीक भविष्यवाणी संसाधनों और बहुमूल्य जीवन को बचाने में मदद करती है। उन्होंने पर्यावरण विज्ञान विभाग के काम की भी सराहना की जो राज्य के छह जिलों के लिए मौसम पूर्वानुमान से कृषि-सलाहकार बनाने का कार्य कर रहा है। डॉ. ठाकुर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चुनौतियों से उबरने और भविष्य के लिए एक सुरक्षित विश्व के साझा दृष्टिकोण को हासिल करने में मदद करने के लिए जलवायु कार्रवाई में अग्रणी कार्य करते रहेंगे। डॉ. एमएस जांगड़ा ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषक समुदाय के लिए मौसम पूर्वानुमान और कृषि-सलाह के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया जिसमें 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने विजेताओं समृति दत्ता, विपाशा शर्मा और जसवन्त को पुरस्कार दिये।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री ने होली उत्सव की बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तथा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को होली उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि रंगों के त्योहार होली का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। उन्होंने आशा जताई कि यह त्योहार भाईचारे की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता तथा अखण्डता को और मज़बूती प्रदान करेगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बधाई सन्देश में कहा कि होली उत्सव को हर संप्रदाय एवं धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द को और मज़बूत बनाने में सहायता मिलती है।

राज्यपाल ने सुजानपुर में राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। हमीरपुर ज़िले की ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर का चार

दिवसीय राष्ट्रस्तरीय होली उत्सव शनिवार को पारंपरिक भव्य शोभायात्र एवं पूजा-अर्चना के साथ आरंभ हो गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया और ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में विधिवत् पूजा-अर्चना के साथ उत्सव का शुभारंभ किया।

उन्होंने सुजानपुर के चौगान में विभिन्न विभागों, संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन भी किया।

राज्यपाल ने इस अवसर पर लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सबके मंगलमय जीवन की कामना की।

इससे पहले, सुजानपुर पहुंचने पर राज्यपाल का राष्ट्र स्तरीय होली आयोजन समिति के अध्यक्ष एवं हमीरपुर के उपायुक्त अमरजीत सिंह, एसपी पदम चंद, एडीसी मनेश यादव, एसडीएम एवं मेला अधिकारी डॉ. रोहित शर्मा, मेला पुलिस अधिकारी एएसपी राजेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया तथा उन्हें उत्सव से संबंधित परंपराओं एवं प्रबंधों से अवगत करवाया।

राज्यपाल ने बिलासुपर नलवाड़ी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। बिलासपुर में आयोजित राज्यस्तरीय नलवाड़ी उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि नलवाड़ी राज्य का एक पारंपरिक

त्योहार है जो विशेषकर छींज (कुश्ती मुकाबले) के कारण वर्षों से प्रसिद्ध है।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश न केवल देवभूमि है बल्कि उच्च सांस्कृतिक मूल्यों का पोषक भी है। नलवाड़ मेला न केवल इस जिले की समृद्ध कला, संस्कृति को दर्शाता है बल्कि लोगों की सरल और उमंग भरी जीवनशैली का भी परिचायक है।

शुक्ल ने मेला आयोजन समिति को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों के दैनिक जीवन में मेले और त्यौहार महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नलवाड़ी मेले के दौरान आयोजित होने वाली अन्य गतिविधियों में कुश्ती प्रतियोगिता एक प्रमुख आकर्षण है। उन्होंने कहा कि मेलों और उत्सवों में आयोजित होने वाली खेल गतिविधियां युवाओं को खेलों की ओर मोड़ने तथा उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है।

राज्यपाल ने इस मौके पर प्रत्येक मतदाता से आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने पारंपरिक छींज मुकाबला भी देखा।

राज्यपाल ने कुश्ती मुकाबलों के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करने के बाद महोत्सव के समापन की घोषणा की।

पुलिस अधीक्षक विवेक चहल ने ऐतिहासिक नलवाड़ी मेले के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

भाजपा की चाल, चेहरा, चरित्र प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब:कांग्रेस

शिमला/शैल। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा की चाल, चेहरा और चरित्र हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने बेनक़ाब हो गया है। कांग्रेस के बाग़ी विधायकों के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस पूरे

षडयंत्र के पीछे भाजपा नेताओं का सत्ता लोभ ही था। भाजपा की शह पर ही बाग़ियों ने लोकतांत्रिक तरीक़े से चुनी गई सरकार को गिराने की साज़िश रची और जन भावनाओं से खिलवाड़ किया है। यही नहीं, भाजपा के प्रभाव में आकर ही बागियों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के विरुद्ध वोट दिया।

मंत्रियों ने कहा कि वह नेता कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, जिन्हें पार्टी ने हाथ के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जितवाया, सम्मान दिया और विभिन्न पदों पर सुशोभित किया। सत्य यह है कि सभी बागी निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस पार्टी से बाहर गए हैं और इसका प्रदेश की जनता के हित से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अपनी मां का दर्जा देने वालों ने अपनी मां की पीठ में छुरा घोंपा है और भाजपा की कठपुतली बन गए हैं। छह बागी विधायकों ने प्रदेश के इतिहास में अवसरवादी राजनीति का एक काला अध्याय जोड़ दिया है, जिसके लिए उन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ़ नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सवा साल के छोटे से कार्यकाल में चुनाव के दौरान दी गई दस गारंटियों में से पांच को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में ही 22 हजार से अधिक पद भरे जा रहे हैं और स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए 680 करोड़ रुपए की स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है। सरकारी कर्मचारियों के साथ किए गए वादे को निभाते हुए पहली ही कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा भी पूरा कर दिया गया है। दूध पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है।

मंत्रियों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर चुनौती का सामना करने में समक्ष है और पार्टी के सभी नेता व कार्यकर्ता एकजुट हैं। जनता ही कांग्रेस पार्टी की ताक़त है। आने वाले लोकसभा

चुनाव और उपचुनाव में प्रदेश के मतदाता धन-बल की राजनीति को करारा जवाब देगी। कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतर से विजयी होंगे और प्रदेश की जनता स्वार्थी ताक़तों और लोकतंत्र का मज़ाक़ बनाने वालों को सबक़ सिखाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता का समर्थन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है और हिमाचल प्रदेश में आया राम-गया राम की संस्कृति नहीं चलेगी।

भाजपा महिला विरोधी:जगत सिंह नेगी

शिमला/शैल। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर महिला विरोधी हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत महिलाओं को मिलने जा रहे 1500 रुपये से विपक्ष पूरी तरह बौखला गया है। इस योजना का लाभ प्रदेश में पहली अप्रैल 2024 से प्रदान करने की औपचारिकताएं चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले पूरी हो चुकी हैं।

नेगी ने कहा कि योजना के लिए बजट का प्रावधान किया जा चुका है, मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। योजना को लागू करने की अधिसूचना सरकार जारी कर चुकी है। अगर महिलाएं अब फार्म जमा कर रही हैं तो भाजपा और जयराम ठाकुर क्यों विरोध कर रहे हैं। उन्हें महिलाओं को बताना होगा, क्या वह चाहते हैं कि 18 साल से अधिक आयु की पात्र बेटियों, बहनों और माताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष को लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार साफ नजर आ रही है, इसलिए वह महिलाओं के विरोध में

आ खड़े हुए हैं। प्रदेश की महिला शक्ति उन्हें इस विरोध का मुंहतोड़ जवाब देगी और आगामी चुनावों में भाजपा को चारों खाने चित करेगी।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सवा साल के कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किया है, दस में से पांच गारंटियों को भी पूरा कर दिया गया है। इससे भाजपा नेता बौखलाहट में हैं, उन्हें सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन रास नहीं आ रहा। भाजपा व जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के हित में लागू की जा रही नीतियों का विरोध करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए।

निर्दलीयों के विधायकी छोड़ने से खड़े हुए कई सवाल:कांग्रेस

शिमला/शैल। कांग्रेस विधायक संजय रत्न एवं हरीश जनारथा ने तीन निर्दलीयों के विधायकी छोड़ने पर सवाल

खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि निर्दलीयों को अपने चुनाव क्षेत्र की जनता को बताना होगा कि विधायकी छोड़ने के पीछे आखिर उनकी क्या मजबूरी है। क्यों जनता पर उप-चुनाव का बोझ थोपा जा रहा है। दोनों ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को हराकर मतदाताओं ने उन्हें पूरे पांच वर्ष के लिए निर्दलीय विधायक बनाया था, तो ऐसे में उन्होंने सवा साल के भीतर ही किस दबाव में विधानसभा की सदस्या छोड़ी है। क्यों वह अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की भावनाओं का अपमान कर रहे है।

उन्होंने कहा कि इन सवालों के जवाब तीनों निर्दलीय विधायकों को देने होंगे। निश्चित रूप से तीनों ने प्रदेश की जनता की भावना से खिलवाड़ किया है और उन्हें प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। संजय रत्न और हरीश जनारथा ने कहा कि निर्दलीयों ने वर्तमान राज्य सरकार से अपने चुनाव क्षेत्र के लिए अनेकों कार्य करवाए और वह काम न होने की बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में भाजपा का असली चेहरा भी प्रदेश की जनता के सामने आ रहा है। भाजपा किस प्रकार से धन-बल के माध्यम से वर्ष 2022 के जनादेश का अपमान करने में लगी है, यह प्रदेश की जनता के सामने है। दोनों ने कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र और लोकतंत्र की भावना

का मज़ाक़ बना दिया है। सत्ता के लालच में भाजपा ने देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यह तमाशा हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है तथा इन कृत्यों के लिए निर्दलीयों और भाजपा दोनों को ही सबक़ सिखाएगी।

जल्द होंगे चारों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित:ठाकुर राम लाल

शिमला/शैल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री ठाकुर राम लाल ने कहा है कि जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश के चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है और प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपनी विजय का परचम लहरायेगी।

ठाकुर राम लाल ने मीडिया में चल रही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी के एक प्रश्न के उत्तर में साफ किया कि वह पहले भी एक बार इस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके है। उन्होंने कहा कि न तो उन्होंने पहले कभी इस संसदीय क्षेत्र से पार्टी टिकट का आवदेन किया था और न ही अब किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी आलाकमान व सीईसी ही करती है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही है और उन्हें जो भी आदेश होता है उसका वह पालन करते है।

ठाकुर राम लाल ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के चलते कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश में छ: सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिये ही

इसका गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि अभी समिति की कोई बैठक नही हुई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी बैठक होगी और संगठन व सरकार के बीच ओर बेहतर तालमेल स्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरी तरह मजबूत है और अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।

शान्ता कुमार की सलाह पर चिंतन करें सत्ता के लोभी भाजपा नेता:पठानिया

शिमला/शैल। डिप्टी चीफ व्हीप केवल सिंह पठानिया ने भाजपा नेताओं को पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की सलाह पर चिंतन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता शान्ता कुमार का यह कथन बिल्कुल सही है कि सिर्फ राम

मंदिर का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें भगवान राम के आदर्शों को जीवन में अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को भुलाकर धन-बल और अन्य हथकंडे अपनाकर सत्ता हथियाने की साज़िशें रच रहे हैं। भाजपा को न नैतिकता की परवाह है और न ही भगवान राम के आदर्शों की, बल्कि उनके नेताओं सत्ता मोह में फँसे हैं।

केवल सिंह पठानिया ने कहा कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जबकि भाजपा नेता मर्यादाओं को तार-तार कर घटिया स्तर की राजनीति पर उतारू हैं। आज भाजपा का दूर-दूर तक भगवान राम से कोई नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के छ: बाग़ियों और तीन निर्दलीयों का भाजपा में शामिल होना, इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार गिराने की साज़िशों के सूत्रधार हिमाचल भाजपा के नेता हैं। भाजपा ने ही उन्हें हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन की सैर कराई और एक महीने तक उन्हें महंगे फाइव स्टार होटलों में ठहराने के लिए करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च की। उन्होंने कहा कि आज भाजपा नेता 9 पूर्व विधायकों को अपनी पार्टी में जोड़कर जश्न मना रहे हैं, नाटियां डाल रहे हैं लेकिन अपनी पार्टी में सुलग रही चिंगारी को वह देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं। भाजपा नेता यह भी भूल रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता-जनार्दन ही सर्वोपरी है। अंतत: सभी को जनता की अदालत में जाना होगा और प्रदेश के मतदाता लोकतंत्र के साथ हुये इस भद्दे मज़ाक़ को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को प्रदेश के मतदाता सबक़ सिखाने को तैयार बैठे हैं और जनादेश का अपमान क़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ताक़त प्रदेश की जनता है और जनता का पूरा आशीर्वाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के साथ है। उन्होंने कहा कि जनता के स्नेह से वर्तमान सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी और भाजपा की कोई भी साज़िश कामयाब नहीं होगी।

सत्ता लोभ में जयराम ठाकुर कर रहे जनादेश का अपमान : बाली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन

रघुबीर सिंह बाली ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, सत्ता के बिना मछली की तरह छटपटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष इस जनादेश को पचा नहीं पा रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के गठन के बाद से ही भाजपा नेता ऑपरेशन लोट्स की बात बार-बार खुलेआम दोहरा रहे हैं और वर्तमान राज्य सरकार को अस्थिर करने की साज़िश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर को सत्ता लोभ छोड़कर जनादेश को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए और पूरे पांच साल एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पूरी तरह से टिकाऊ है और भाजपा की कोई भी साज़िश कामयाब होने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपने पांच वर्ष का कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी।

जब लोग तुम्हे गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

देश में अमीर और गरीब का अन्तराल क्यों बढ़ रहा है

एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के मुताबिक़ भारत की कुल दौलत का चालीस प्रतिशत केवल एक प्रतिशत लोगों के पास है। एक व्यक्ति के पास सौ में से चालीस हो जाये और शेष निनावे लोगों के एक रूपये से भी कम प्रति व्यक्ति संपत्ति हो तो उस देश में अमीर और गरीब के बीच में बढ़ते अन्तराल का अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्र से राज्यों तक हर सरकार प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण करती है। इस सर्वेक्षण में प्रतिव्यक्ति आय और ऋण का आंकड़ा जारी किया जाता है। इस आंकड़े के मुताबिक भारत में प्रतिव्यक्ति निश्ल राष्ट्रीय आय वर्ष 2023-24 में 1,85,854 रूपये अनुमानित है। हिमाचल में प्रतिव्यक्ति आय 2022-23 में 2,18,788 रुपए रही है। आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आय के इन आंकड़ों को झूठलाया नहीं जा सकता। लेकिन क्या व्यवहार में यह आंकड़े कहीं मेल खाते हैं? केंद्र और राज्य केआंकड़ों को एक साथ रखकर हिमाचल में प्रतिव्यक्ति आय चार लाख से बढ़ जाती है। इसमें यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जिस प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय चार लाख हो उस प्रदेश की सरकार को विकास के लिये कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों होगी। लेकिन आज हिमाचल में प्रति व्यक्ति कर्ज का आकड़ा भी लगभग आय के बराबर ही हो गया है।

ऐसा इसलिये है कि आंकड़ों की इस गणना का आम आदमी के साथ व्यवहारिक रूप से कोई सीधा संबंध ही नहीं है। कोई भी सरकार व्यवहारिक रूप से दस प्रतिशत लोगों के लिये ही काम करती है। आम आदमी के विकास के नाम पर कर्ज लेकर केवल 10 प्रतिशत के लाभ के लिये ही काम किया जाता है। एक उद्योगपति के बड़े निवेश से राज्य की जीडीपी बढ़ जाता है। उसके लाभ से ही प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा बढ़ जाता है। आय और कर्ज के बढ़ते आंकड़ों के इस खेल में सरकारों में स्थायी और नियमित रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। चुनावों में मुफ्ती की घोषणाओं के साथ समाज में लाभार्थियों के छोटे-छोटे वर्ग खड़े किए जा रहे हैं। आज कर्ज विश्व बैंक आईएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय एजैन्सियों से सरकारें बाहय सहायता प्राप्त योजनाओं के नाम पर ले रही है। जिन योजनाओं के लिये यह कर्ज लिया जा रहा है उनके कार्यन्वयन के लिये ग्लोबल टैन्डर की शर्तें रहती हैं। अभी शिमला में 24 घंटे जलापूर्ति के लिये विश्व बैंक से 460 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी और इसमें ग्लोबल टैंडरिंग के नाम पर उसका ठेका एक विदेशी कंपनी को शायद 870 करोड़ में दे दिया गया। इसमें कैसे क्या हुआ का प्रसंग छोड़ भी दिया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है की किस तरह से आम आदमी के नाम पर कर्जा बढ़ाया जा रहा है। ऐसे सैकड़ो उदाहरण केंद्र से लेकर राज्यों तक उपलब्ध हैं।

आज केंद्र से लेकर राज्यों तक की सभी योजनाओं पर यह सवाल उठाता है कि आम आदमी के नाम पर लिये जा रहे कर्ज के लभार्थी कुछ मुठी भर लोग क्यों हो रहे हैं। केंद्र से लेकर राज्यों तक कोई भी सरकार रोजगार के वायदों को पूरा क्यों नहीं कर पा रही है? मुफ्त राशन पाने वालों का आंकड़ा लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्ति के लिए मुफ्ती की घोषणाओं और धार्मिकता का सहारा क्यों लेना पढ़ रहा है? आज सरकार को नई शिक्षा नीति लाते हुये उसकी भूमिका में ही क्यों लिखना पड़ रहा है कि इस शिक्षा के बाद खाडी के देशों में बतौर मजदूर हमारे युवाओं को रोजगार बड़े अवसर उपलब्ध होंगे। क्या आज देश के नीति नियन्ताओं से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिये की अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार देश में गरीब और अमीर के बीच का अंतराल लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? इस बढ़त का अंतिम परिणाम क्या होगा?

CAA : वसुधैव कुटुम्बकम् को चरितार्थ करता एक भारतीय कानून

गौतम चौधरी

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा संशोधित कर बनाया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम, वसुधैव कुटुम्बकम् को चरितार्थ करता मानवता को परिपुष्ट करने वाला एक भारतीय कानून है। यह कानून भारतीय संसद द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को बनाया गया था। जिसके बाद असम समेत पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। विपक्षी दलों द्वारा मुसलमानों को यह कहकर भ्रमित किया गया कि सीएए से उनकी नागरिकता को खतरे में पड़ जाएगी। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी एवं धर्मगुरुओं के द्वारा भी कुछ इसी प्रकार की बातें समाज में प्रचारित और प्रसारित की गयी। लेकिन क्या यह सत्य है? इस मामले में केंद्रीय गृहमंत्रालय कई बार स्पष्टीकरण दे चुका है। सीएए द्वारा किसी की भी नागरिकता खत्म नही की जा सकती है, बल्कि यह नागरिकता देने वाला कानून है। चूंकि विपक्ष द्वारा बार-बार मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी कह कर प्रचारित किया जाता रहा है, इसीलिये मोदी विरोध में मुसलमानों को भ्रमित कर सीएए के खिलाफ जगह-जगह धरना, विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गए। अगर कोरोना महामारी ना आती, तो संभव था कि सीएए विरोध में होने वाला आन्दोलन लंबा खिंचता।

खैर! अब केंद्र सरकार ने सीएए को धरातल पर उतार दिया है। हालांकि यह प्रश्न जरूर है कि आखिर इतने प्रभावशाली और व्यापक चिंतन को आत्मसात किए इस कानून को धरातल पर उतारने में इतना वक्त क्यों लगा? यह सवाल न केवल प्रतिपक्षियों के द्वारा पूछे जा रहे हैं अपितु मुसलमान बुद्धिजीवी भी इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। चलो जब यह कानून लागू कर दिया गया तो इससे आपत्ति किसे होनी चाहिए? विपक्षी पार्टियां तो इसलिए आपत्ति दर्ज करा रही है कि उन्हें सत्ता फिर से प्राप्त करना है लेकिन बिना कुछ समझे मुसलमान मुसलमान लामबंद होने लगे हैं। सपा के प्रवक्ता ने सीएए के विरोध में शाहीनबाग दोहराने की चेतावनी दी, तो कई अन्य संगठन व व्यक्तियों द्वारा सीएए के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। सवाल यही से पैदा होता है? जब सीएए से किसी की नागरिकता जाने का सवाल ही नही तो फिर इसका विरोध किसलिए? जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्पष्ट कह चुके हैं कि, हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए हैं। यह किसी की भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने के लिए नही है। ऐसे में इस मामले में विरोध का मामला पूरी तरह राजनीतिक प्रतीत होता है।

केंद्रीय गृहमंत्री के इस आश्वासन के बावजूद सीएए के विरोध में लोगों को भ्रमित करने का षड़यंत्र जारी है। वास्तविकता यह है कि मुद्दाविहीन विपक्ष और नरेन्द्र मोदी को हराने में अभी तक पूरी तरह नाकाम रहने वाले नेता अपनी लड़ाई मुसलमानों के सिर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को इस षड़यंत्र को पहचानना होगा और एक बार खुद से भी सवाल करना होगा कि अभी तक मोदी सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आयी है क्या उसमें मुसलमानों से भेदभाव किया गया है? मेरी समझ में तो ऐसा कुछ नही है। बावजूद इसके कुछ सियासी दल अपने निजी स्वार्थ के लिए मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने पर तुले हैं। जहां तक सीएए का सवाल है, वह नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता लेने का। क्या इस सच्चाई से इंकार किया जा सकता है कि पाकिस्तान, बंग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। इन तीनों पड़ोसी देशों से प्रताड़ित होकर अपनी जान बचाकर भारत आए शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जा रही है, तो इसमें गलत क्या है? यहां के मुसलमानों को इसका स्वागत करना चाहिए और मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मुसलमानों को यह नही भूलना चाहिए कि जब यूरोप में यहूदियों के खिलाफ अत्याचार होने लगा तो खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब ने उन्हें अरब में आकर बसने की बात कही थी। यूरोप में जब यहूदियों पर अत्याचार बढ़ा तो औटोमन सुल्तान ने यहूदियों को तुर्की के इस्ताबुल और कस्तूतूनिया में लाकर बसा दिया था। भारतीय हुक्मरान यही तो कर रहे हैं। जहां तक मुसलमानों की बात है तो इन तीन देशों में मुसलमान उतने प्रताड़ित नही हैं, जितने इसाई, हिन्दू, पारसी, सिख, जैन और बौद्ध। इसका मुसलमानों को ख्याल रखना होगा। फिर विदेशी मुसलमानों के लिए अलग से नागरिकता का कानून भारत सरकार ने बना कर रखा है। उसके तहत बाहर के देशों के मुसलमान नागरिकता प्राप्त भी कर रहे हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की जमीनें हमेशा तंग रही हैं, उन्हे सताए हुए लोगों को भारत की सरकार भारत की नागरिकता देने के लिए सीएए लेकर आयी है। जाहिर है, उन धार्मिक अल्पसंख्यकों में मुस्लिम नही हैं, इसलिए मुस्लिमों को सीएए से बाहर रखा गया।

सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम छह समुदायों को नागरिकता देने का प्रावधान किया है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक एक अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक इन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गयी है। जिन 9 राज्यों में नागरिकता दी गई है, उनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम शामिल है। अब सरकार व्यापक स्तर पर सीएए लागू करेगी, ताकि प्रताड़ित होकर भारत में शरण लेने वाले उक्त धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देकर उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके।

भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् की रही है, आज दुनिया हसरत भरी निगाह से भारत की ओर देख रही है। शायद इसीलिये पड़ोसी देशों में प्रताड़ित होने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, इसाई, जैन और पारसी ने शरण लेने के लिए भारत को चुना। उनकी उम्मीदों पर खरा अगर वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी महान संस्कृति वाला देश नही उतरा तो फिर कौन उतरेगा? इस सवाल के साथ ही यहां फिर से दोहराना जरूरी है कि किसी मुसलमान को सीएए का विरोध करने की जरूरत नही है। यह मुसलमानों के खिलाफ नही है। इस मुद्दे पर भारतीय मुसलमान विपक्षी दलों का हथियार बनने से बचें। उनके भ्रमजाल में न फंसे और तहे दिल से इस कानून का स्वागत करें।

हिमाचल प्रदेश की बहनों के साथ धोखा या फिर चालाकी का दूसरा दौर

शिमला। हिमाचल प्रदेश का 2022 का विधान सभा चुनाव आंखे खोल देने वाला है। हिमाचल की जनता

पूर्व भाजपा सरकार से संतुष्ट थी और स्पष्ट था कि भाजपा ही दोबारा सत्ता में आएगी परन्तु कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए लोक लुभावने नारे लगाये और आनन – फानन में दस प्रकार की गारंटियां दे डाली व लम्बा चौड़ा घोषणा पत्र लिख डाला। इन गारंटियों के रचयिता ।नजीवत व घोषणा पत्र के सम्पादक सभी ने केवल पैंतरा फैंका कि ''लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का''।

कांग्रेस की ये गारंटियां पूर्व भाजपा सरकार के बेहतरीन कार्यो पर भारी पड़ गई और झूठी गारंटियों का तीर चल गया और सच्ची सेवा पिछड़ गई। सरकार कांग्रेस की बन गई, सुखविन्द्र जी मुख्यमंत्री बन गए। अब भाजपा की आवाज बुलंद हो गई कि झूठी गारंटियां कहां गई और जनता में दिए गए कांग्रेसी नेताओं के बयान कि पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार मिलेंगे आदि – आदि। सुखविन्द्र सुक्खू सरकार ने अपनी साख बिगड़ती देख विधान सभा में एक श्वेत पत्र रख दिया और कहा कि भाजपा की सरकार 70 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ गई है, खजाना खाली है इसलिए गारंटियां पूरी नहीं की जा सकती।

श्वेत पत्र का सत्य भी जनता के सामने आ गया कि 70 हजार करोड़ रूपये में से 50 हजार करोड़ रूपये कांग्रेस पार्टी की सरकारों का है और फिर श्री सुखविन्द्र सिंह सरकार ने दनादन लोन लेना शुरू कर दिया और 15 महीनों की सरकार ने 15 हजार करोड़ रूपये का लोन ले लिया। सरकार का यह पैंतरा भी फेल हो गया। भगवान भी नाराज हो गए और प्रदेश में अचानक आपदा आ गई। अब आपदा में जनता की सेवा करने की बजाए भाजपा को कोसना शुरू कर दिया कि केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। वह झूठ भी जनता के सामने आ गया। केवल आपदा राहत में हजारों करोड़ रूपये व 21 हजार मकान प्रदेश सरकार को केन्द्र की मोदी सरकार ने दिए जिसका दुरूपयोग कांग्रेस सरकार कर रही है और भी खुलासा हो गया एक लाख करोड़ रूपये सड़कों के निर्माण का, मनरेगा का, सर्व शिक्षा अभियान का, वैलफेयर का, ग्रामीण सड़कों का, पेयजल का, सीवरेज का, शहरी एवं ग्रामीण विकास का, हजारों करोड़ रूपये प्रदेश को दनादन आ रहा है, यह जनता को मालूम हो गया और कांग्रेस सरकार बेनकाब हो गई।

प्रदेश सरकार द्वारा सभी विकास कार्य बंद कर दिए गए, खुले हुए संस्थान बंद कर दिए, जनता त्राहि माम – त्राहि माम करने लगी। परिणामस्वरूप 9 विधायक (6 कांग्रेस व 3 आजाद) ने सरकार की खिलाफत का बिगुल बजा दिया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि 40 + 3 विधायकों की सरकार 68 में से 34 पर अल्पमत में आकर खड़ी हो गई। केवल 15 महीनो में अर्थात कांग्रेस का व सरकार का समूचा नेतृत्व बुरी तरह से फेल हो गया। अब कांग्रेस की खजूर पर लटकी सरकार को बचाने के लिए कैबिनेट के पद धड़ाधड़ बांटे जा रहे हैं। अब न कर्जा रहा है, न पैसे की कमी है, न गाड़ियों की, न बंगलों की। अब जैसे – तैसे करके सरकार बचानी है, यही एक मात्र कदम है।

महिलाओं को 1500 रूपये महीने देने वाली गारंटी का मामला खूब उछल गया और लोकसभा चुनाव भी आ गया तो फिर एक बार गारंटियों का पिटारा खोल दिया गया। खुल जा सिम – सिम – 1500 रूपये के फॉर्म बाहर आने लगे। बहनों ने फॉर्म भरने शुरू कर दिए। पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी गई है कि प्रदेश की 27 लाख मतदाता बहनों को येन केन प्रकरेण विश्वास दिला दिया जाये। कांग्रेस सरकार का केवल एक ही लक्ष्य शेष रह गया है कि लोकसभा चुनाव में दोबारा से प्रदेश की जनता को झूठे लुभावने वादों से ठगना और वोट लेना।

'22 गोइंग टू 72' अभियान से बढ़ेगा मतदान प्रतिशत

शिमला/शैल। निर्वाचन विभाग हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 2019 के आम चुनावों में 70 प्रतिशत से कम मतदान दर्ज करने वाली 22 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर '22 गोइंग टू 72' अभियान की शुरूआत की है। इसका उद्देश्य पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान प्रतिशत 72.42 में इस बार वृद्धि करना है।

यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने दी।

उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत विभिन्न अराजनीतिक लोगों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए क्षेत्रवार निर्वाचन आइकन के रूप में शामिल किया जाएगा और बच्चों द्वारा बनाए गए निमंत्रण कार्ड भी मतदाताओं को वितरित किए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए बूथ जागरूकता क्लबों को सक्रिय किया जाएगा और चुनावी साक्षरता क्लब चुनावी साक्षरता अभियान चलाएंगे ताकि आम जनता को बढ़चढ़ कर मतदान के लिए प्रेरित किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक संगठनों में मतदाता जागरूकता मंच भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से पिछले आम चुनावों में सवैतनिक अवकाश के बावजूद मतदान न करने की वजह भी पूछी जाएगी। चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। यह नोडल अधिकारी इस बात की पुष्टि करेंगे कि मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश की सुविधा दिए जाने के बावजूद कितने कर्मचारियों ने वास्तव में मतदान में भाग लिया है।

सांस्कृतिक गतिविधियों के अलावा हस्ताक्षर अभियान को भी विस्तृत स्तर पर चलाया जाएगा।

ACs in LSE-2019 where VTR Less Than 70%

Sr. No.	Name of District	Assembly Constituencies	VTR Less than 70%
1	Chamba	2-Bharmour (ST)	64.53
2	Chamba	4-Dalhousie	69.07
3	Chamba	5-Bhattiyat	66.66
4	Kangra	10-Dehra	68.07
5	Kangra	11-Jaswan-Pragpur	69.70
6	Kangra	13-Jaisinghpur (SC)	63.73
7	Kangra	19-Palampur	69.18
8	Kangra	20-Baijnath (SC)	64.62
9	Kangra	14-Sullah	70.26
10	Lahaul & Spiti	21-Lahaul & Spiti (ST)	63.03
11	Mandi	31-Jogindernagar	67.04
12	Mandi	32-Dharampur	62.74
13	Mandi	35-Sarkaghat	67.14
14	Hamirpur	36-Bhoranj (SC)	69.58
15	Sirmour	59-Shillai	69.69
16	Sirmour	57-Sri Renukaji (SC)	70.13
17	Shimla	60-Chopal	67.07
18	Shimla	61-Theog	67.79
19	Shimla	62-Kasumpti	66.41
20	Shimla	63-Shimla	64.01
21	Shimla	64-Shimla Rural	67.74
22	Shimla	66-Rampur (SC)	69.94

टीबी को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए खुला संवाद जरूरी: डीसी

शिमला। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि टीबी रोग को लेकर समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए खुला संवाद जरूरी है इसमें सभी नागरिकों को अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि कांगड़ा जिला को टीबी मुक्त बनाया जा सके। शनिवार को 'विश्व क्षय रोग दिवस' के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम तथा यूनियन संस्था के सहयोग से उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में आयोजित एक दिवसीय वर्कशॉप की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त हेमराज बैरवा ने लोगों से जिला में क्षय रोग टीबी के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने का आहवान किया है। उन्होंने टीबी उन्मूलन के संकल्प को पूरा करने में बहुक्षेत्रीय सहभागिता पर भी बल दिया।

उपायुक्त ने कहा कि साल 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के संकल्प के साथ काम किया जा रहा है। कांगड़ा जिला इसमें अपनी भूमिका निभाने को तत्पर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में टीबी के लिए नैदानिक क्षमता में काफी वृद्धि के साथ डायग्नोस्टिक सुविधा की मजबूती पर बल दिया गया है। जिले में 47 सक्रिय टीबी डायग्नोस्टिक केंद्र हैं। जिलाधीश ने टीबी समाप्त करने के लिए टीबी परीक्षा दर में वृद्धि करने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से टीबी की पहचान पर बल देने, टीबी निवारक उपचार व्यवस्था को मजबूत करने को कहा। साथ ही दवा प्रतिरोधी टीबी में कमी लाने, सामुदायिक भागीदार के लिए रणनीति निर्माण, बहुक्षेत्रीय सहभागिता और सामाजिक कॉर्पोरेट गतिविधियों का बढ़ावा देने तथा टीबी मुक्त भारत अभियान को और गति से आगे बढ़ाने और बीमारी के कारण होने वाले जेब खर्च को कम करने के लिए कार्य करने पर बल दिया।

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने आम नागरिकों से नि – क्षय मित्र बनकर टीबी उन्मूलन में अपना सहयोग देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाईयां नि – क्षय मित्र बनकर टी.बी रोगियों की सहायता को आगे आएं और टी.बी मुक्त कांगड़ा बनाने के संयुक्त प्रयासों में सहयोगी बनें। उपायुक्त ने कहा कि क्षय रोग असाध्य रोग नहीं है। रोग की शीघ्र और सही जांच के बाद सफल उपचार से टी.बी को हराना संभव है।

जिला क्षय रोग अधिकारी डा सूद ने बताया कि नि – क्षय मित्र के रूप में पंजीकरण के लिए नि – क्षय पोर्टल पर एक वेब पेज कम्यूनिटीस्पोर्ट डॉट निक्षय डॉट आइएन बनाया गया है। इस पर पंजीकरण करने पर एक विशिष्ट आईडी मिलती है जिसके अनुसार खंड चिकित्सा अधिकारी या जिला क्षय रोग अधिकारी नि – क्षय मित्र से संपर्क करके उनके साथ सामुदायिक सहायता प्राप्त करने के लिए सहमति देने वाले सक्रिय टी.बी रोगियों की सूची साझा करते हैं। नि – क्षय मित्र उसके अनुसार सहायता का विकल्प चुन सकते हैं। इस अवसर पर टीबी चौपिंयन्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुशील शर्मा ने जिले में टीबी उन्मूलन के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। इस अवसर पर टीबी उन्मूलन में बेहतरीन सहयोग देने वाले सीएचओ, आंगनबाड़ी वर्कर्स को सम्मानित भी किया गया।

बैठक में यूनियन संस्था के प्रतिनिधि प्रवीण कुमार, गूंजन के डायरेक्टर विजय कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक उपस्थित रहे।

शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में चुनावी रैलियों की अनुमति नहीं:डीसी

शिमला। लोकसभा निर्वाचन – 2024 के दृष्टिगत सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में चुनावी रैलियां करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी हेमराज बैरवा ने देते हुए बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों के अलावा अन्य स्थानों पर भी चुनावी रैलियों के लिए अनुमति लेना जरूरी है ताकि कानून तथा व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें।

उन्होंने कहा कि चुनावी रैलियों की विडियोग्राफी करने का प्रावधान भी किया गया है ताकि चुनावी रैली पर होने वाले खर्च का अनुमान भी लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि रैलियों के लिए टैन्ट, कुर्सियां, ध्वनि यंत्रों इत्यादि की दरें भी निर्धारित की गई हैं उसके आधार पर ही राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशी को रैलियों का खर्चा दर्शाना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के लिए व्यय सीमा 95 लाख निर्धारित की गई है इससे अधिक व्यय नहीं किया जा सकता है। इस बाबत व्यय पर निगरानी रखने के लिए व्यय निगरानी समिति भी गठित की गई है इसके साथ ही चुनाव आयोग की तरफ पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए जाएंगे ताकि निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव संपन्न करवाए जा सकें।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, पोस्ट आफिस, एयरपोर्ट, पुलों, सरकारी बसों, सरकारी भवनों, विद्युत तथा दूरसंचार विभाग के खंभों, शहरी निकायों के भवनों पर राजनीतिक पार्टियां के दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री लगाने की पूर्ण पाबंदी है।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में नोमिनेशन से दस दिन पहले तक नाम शामिल किए जा सकते हैं इस के लिए जिला भर में मतदाता जागरूकता अभियान भी आरंभ किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके।

हमने बसाए 22 हजार आपदा प्रभावित परिवार, भाजपा बताए अपना योगदानःमुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश

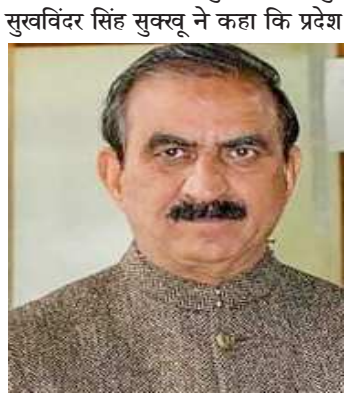

सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश के 22 हजार से अधिक आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने बिना केंद्र सरकार की सहायता के आपदा प्रभावितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 4500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज जारी किया, जिससे हजारों आपदा प्रभावितों की मदद हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेताओं को हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने अपना योगदान बताना चाहिए। हिमाचल के भाजपा नेता केंद्रीय मदद मिलने में लगातार अड़ंगे लगाते रहे, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कोई भी विशेष पैकेज नहीं दिया गया है। जबकि बागी विधायकों को हिमाचल प्रदेश से बाहर महँगे फाइव स्टार होटलों में ठहराया जा रहा है, हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन की सैर कराई जा रही है तथा उनकी सुरक्षा पर भी भाजपा भारी-भरकम पैसा खर्च रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब भी हिमाचल के हितों की बात आई, भाजपा नेताओं ने अपना हिमाचल विरोधी चेहरा दिखाया। प्रदेश की जनता अब भाजपा नेताओं से जवाब मांग रही है लेकिन उनसे भाजपा से जवाब देते नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जब हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने व विशेष राहत पैकेज देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो भाजपा नेता चर्चा के दौरान तीन दिन तक बड़ी-बड़ी बातें करते रहे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। क्या ये लोग हिमाचल के हितैषी हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कभी किसी राजनीतिक लाभ की मंशा से काम नहीं करती क्योंकि हमारे कर्म में मानवता और सेवाभाव सर्वोपरि है। यही वजह है कि हमने आपदा प्रभावितों की मदद करने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया और 4500 करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान कर आपदा के दौरान पूर्व में प्रदान की जा रही सहायता राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की। किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान घोषित यह ऐतिहासिक राहत पैकेज है। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता राशि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये, दुकान या ढाबे के नुकसान पर सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और गौशालाओं को नुकसान होने पर सहायता राशि को 3 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। इसके अलावा आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी दरों पर निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, निःशुल्क बिजली व पानी कनेक्शन और सरकारी दरों पर सीमेंट भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का हर फैसला जन कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सेवा भाव के साथ कार्य करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के आचरण को प्रदेश की जनता अच्छी तरह से देख रखी है और आने वाले चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी।

भाजपा प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का कर रही प्रयासःराठौर

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि देश मे आज अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवज दबाने के लिए कही उनके बैंक खाते सीज किये जा रहें है तो कही नेताओं

को गिरफ्तार कर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए राठौर ने कहा कि आज देश मे लोकतंत्र व संविधान खतरे में है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। भाजपा एक सोची समझी साजिश के तहत प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है जिसमें वह कभी सफल नही होगी।

कुलदीप राठौर ने कहा कि आज लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गारंटी दें रहे है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनावों में उन्होंने जो दृष्टिपत्र देश के सामने रखा था उसका कोई भी वादा उन्होंने पूरा नही किया। उन्होंने कहा कि न तो किसानों की आय दुगनी हुई, न ही हर साल बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार ही मिले। विदेशों से न तो काला धन ही देश मे आया और न ही हवाई चपल पहनने वालो को जहाज की कोई सुविधा मिली।

राठौर ने कहा कि भाजपा झूठ की बुनियाद पर जुमलेबाजी कर लोगों को गुमराह करती रही है। उनका विरोध करने वालो की आवाज दबाई जाती है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उनके नेता राहुल गांधी को आनन फानन में लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किया गया और उसी बीच उनके सरकारी आवास को खाली तक करवा दिया गया। उन्होंने कहा की न्यायपालिका ने अब तक भाजपा की तानाशाही पर अंकुश लगा रखा है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन बांड से भाजपा ने 12,145 करोड़ से अपना घर भरा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस धन को छुपाने का प्रयास कर रही थी, पर उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एसबीआई को यह सब कुछ सार्वजनिक करना पड़ा है।

राठौर ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान आचार संहिता के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। इसी प्रकार झारखंड के मुख्यमंत्री हमेंत सोरेन को गिरफ्तार कर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया जाता है। उन्होंने कहा की राजनैतिक दलों की तोड़फोड़ करना भाजपा की नीति रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जो कल तक भाजपा को कोसने में कोई कोर कसर बाकी नही रखते थे आज उनके साथ मिलकर उनके परम् मित्र बन गए है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते भाजपा देश मे राजनीतिक अस्थिरता फैलाना का प्रयास कर रही है जो बहुत ही दुखदाई है।

राठौर ने कहा कि कांग्रेस देश के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ किसी भी बलिदान को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस बार देश मे होने वाले लोकसभा चुनाव देश को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि देश मे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।

संरक्षण प्रयासों के लिए प्रकृति विज्ञान को अपनाएंःडा.जोशी

शिमला/शैल। प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन (HESCO) के संस्थापक, डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने युवाओं, विशेषकर

कृषि और वानिकी विषयों के छात्रों के लिए, संरक्षण के लिए प्रकृति विज्ञान को समझने पर जोर दिया। डॉ जोशी गुरुवार शाम को डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी में विश्व वानिकी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर डॉ. जोशी ने वनों और मानव अस्तित्व के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर प्रकाश डाला और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उन प्रथाओं में बदलाव की वकालत की जो पर्यावरण के लिए हानिकारक रही हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉ जोशी ने जलवायु वानिकी में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने पश्चिमी प्रथाओं को आँख बंद करके अपनाने के प्रति आगाह करते हुए स्वदेशी संरक्षण विधियों और आधुनिक दृष्टिकोणों के बीच संतुलन का आहवान किया।

कुलपति प्रो. राजेश्वर सिंह चंदेल ने छोटे किसानों को समर्थन देने, पर्यावरण संरक्षण और स्वदेशी उपज के लिए स्थानीय बाजारों को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए डॉ. जोशी और हेस्को की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में स्थानीय त्योहारों और स्वदेशी प्रथाओं में सतत विकास लक्ष्यों, जिन्हें के वैश्विक संदर्भ में महत्व दिया जा रहा है, को ध्यान में रखा जाता रहा है। इस अवसर पर प्रो. चंदेल ने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न वानिकी और पर्यावरण संरक्षण पहल पर हेस्को के साथ सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

इससे पहले डीन कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री डॉ. सीएल ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत किया और विश्व वानिकी दिवस मनाने के पीछे के उद्देश्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम 'वन और नवाचार: बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान' है। डॉ. ठाकुर ने बताया कि हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जंगल काटे जाते हैं लेकिन इसका केवल एक छोटा प्रतिशत ही वापस उगाया जा रहा है। अनुसंधान निदेशक डॉ. संजीव चौहान ने वनों के वर्तमान महत्व के बारे में जानकारी प्रदान की और बताया कि वे सतत विकास सुनिश्चित करने के जंगल क्यों महत्वपूर्ण हैं। रिमोट सेंलसग, आटिफिशियल इंटेलिजेंस, वन जैव प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के दायरे और संरक्षण प्रयासों में युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम में कविताओं, गीतों और भाषणों के माध्यम से विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमारे जीवन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के साथ-साथ दोनों कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। डॉ. जोशी ने विश्वविद्यालय में की जा रही शोध गतिविधियों के बारे में जानने के लिए विश्वविद्यालय के फार्मों का भी दौरा किया।

क्या भाजपा विधायक .....पृष्ठ 1 का शेष

के मध्यावधि चुनाव करवाये जाने का वातावरण तैयार कर दिया जाये। क्योंकि अभी तक छः मुख्य संसदीय सचिवों की याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई होनी है।

सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि राज्य विधानसभा को ऐसा एक्ट बनाने का अधिकार ही नहीं है। स्मरणीय है कि जब स्व. वीरभद्र सिंह के शासनकाल में प्रदेश उच्च न्यायालय ने तब नियुक्त किये गये मुख्य संसदीय सचिवों और संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देकर इनको रद्द कर दिया था तब सरकार ने उच्च न्यायालय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर करने के साथ ही इस आशय का नया कानून ही बना दिया था। लेकिन उस कानून को तभी उच्चन्यायालय में चुनौती दे दी गयी थी जो अभी तक लंबित चल रही है। इसी कारण से जयराम सरकार में ऐसी नियुक्तियां नहीं हो पायी थी। जयराम सरकार के दौरान सरकार की ओर से यह शपथ पत्र दायर किया गया था कि यदि सरकार ऐसी नियुक्तियां करने का फैसला लेती है तो नियुक्ति करने से पहले उच्च न्यायालय की अनुमति ली जाएगी।

परन्तु अब यह नियुक्तियां करने से पहले उच्च न्यायालय से ऐसी कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गयी है। नये कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर भी साथ ही सुनवानी हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुताबिक इस आश्य का एक्ट बनाने की राज्य विधायकी को अधिकार ही नही है । इस कानूनी जटिलता के साये में यह खतरा बरकरार बना हुआ है की कहीं इन मुख्य संसदीय सचिवों की विधायकी भी न चली जाये। यदि ऐसा होता है तो उनके स्थान पर भी उपचुनाव होने अनिवार्य हो जाएंगे। ऐसे में भाजपा अपने पच्चीस सदस्यों के त्यागपत्र से प्रदेश में मध्यावधि चुनाव करवाने की सभावनाएं पैदा करने का प्रयास करेंगी । वैसे तो कानूनी तौर पर मध्यावधि चुनावों की कोई बाध्यता नहीं होगी। परन्तु ऐसी स्थिति में राजनीतिक अस्थिरता का एक राजनीतिक वातावरण आवश्यक खड़ा हो जाएगा।

राजनीतिक अस्थिरता कोई निश्चित रूप से परिभाषित नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता का संज्ञान लेकर राज्यपाल कोई भी संस्तुति केंद्र को भेज सकता है। ऐसी संस्तुति करने के लिये राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। पूरे भाजपा विधायक दल के त्यागपत्र देने की बात फैला कर यही संदेश देने का प्रयास माना जा रहा है। इससे यह संभावना भी उभर सकती है कि कांग्रेस के जो विधायक और मंत्री अपने को असहज महसूस कर रहे हैं वह पासा बदलने पर विचार करने लग जायें। भाजपा के इस खेल पर पार्टी के ही वरिष्ठतम नेता शान्ता कुमार ने जिस भाषा में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है वह भी इस समय महत्वपूर्ण और प्रासंगिक मानी जा रही है । क्योंकि सत्ता पाने के लिये इस स्तर तक जाने को कोई भी सिद्धांत वादी नेता अपना समर्थन नहीं दे सकता। शान्ता की ही तर्ज पर बहुत से उन लोगों ने जिन्होंने आपातकाल का दौर देखा है और उस समय जेल में गये थे इस तरह के राजनीतिक आचरण को अपना समर्थन नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के असहमति को विरोध करार देकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था ऐसे स्वरों को क्या करना चाहिए था इस पर शान्ता का मौन फिर कई नये प्रश्नों को जन्म दे जाता है।

9 विधायकों का भाजपा द्वारा शिमला पहुंचने पर जोरदार स्वागत

शिमला/शैल। छः विधायक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्य शर्मा भाजपा में शामिल हो गये हैं। इसके साथ ही तीन निर्दलीय आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर,भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल की मौजूदगी में सभी बागी भाजपा में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी मौजूद रहे।

बिंदल ने सभी 9 विधायकों का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा हिमाचल का यह बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब सत्ताधारी दल के 9 विधायक विपक्षी दल की पार्टी में शामिल हुए। इस प्रकार का क्रम कभी भी प्रदेश में नही हुआ।

जयराम ठाकुर ने कहा की हम सभी विधायकों का भाजपा परिवार में स्वागत करते है और इनके पार्टी में आने से पार्टी को बल मिला है। कांग्रेस की सरकार में घुटन का माहौल है और इस कारण सभी विधायक कांग्रेस पार्टी में खुश नहीं है। उन्होंने कहा की कांग्रेस पार्टी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और यह इस कांग्रेस के पत्तन का सबसे बड़ा कारण है।

उसके उपरांत सभी नौ विधायकों का शिमला पीटरहॉफ पहुंचने पर भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया।

सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई विजन नहीं है। कांग्रेस सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करती है। सुधीर शर्मा ने कहा कि जब हम अपने लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो विधायक होने का क्या मतलब है। इसीलिए राज्यसभा चुनाव में हमने हर्ष महाजन को वोट दिया जो हमारे राज्य से हैं। आज हम सब अपनी मर्जी से भाजपा में शामिल हुए हैं। जब किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और आपकी बात सुनने वाला कोई न हो तो ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए।

राणा राजेंद्र राणा ने कहा कि जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, उनकी सुनवाई नहीं हुई। सरकार की ओर से युवाओं को रोजगार देने सहित अन्य मुद्दों पर गौर नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों से की गई गारंटी पूरी नहीं कर रही है। हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन जब लोगों ने हमसे पूछा तो हमारे पास कोई जवाब नहीं था। सीएम तानाशाह बन गए हैं और लोगों को अपमानित कर रहे। विधायकों की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार विधायकों के मुताबिक नहीं चल रही है, बल्कि सुखविन्दर सुक्खू और उनके सहयोगी चला रहे हैं। हिमाचल सरकार वेंटिलेटर पर है। व्यक्ति स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता, सरकार वेंटिलेटर पर। हम मुख्यमंत्री सुक्खू पर मानहानि का दावा करेगे।

रवि ठाकुर ने कहा कि उन्होंने लाहौल-स्पीति की 40 सालों तक बिना किसी स्वार्थ के कांग्रेस में रहकर सेवा की। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमेशा निष्ठा से जुड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार में प्रताड़ना झेलनी पड़ी, मुझे असंविधानिक तरीके से विधानसभा से निलंबित भी किया गया। जब-जब जनता के हक के लिए आवाज उठाई, हमेशा दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और जनता के हक की लड़ाई के लिए आवाज़ उठाता रहूंगा। साथ ही बहुत जल्द लाहौल-स्पीति का दौरा भी करूंगा। रवि ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कुल बजट का 90 फीसदी हिस्सा केंद्र से आता है। यही कारण है कि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र लाहौल-स्पीति को ध्यान में रखते हुए हर्ष महाजन को वोट दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण था विधानसभा अध्यक्ष ने हमें बिना किसी कारण के निलंबित कर दिया।

चैतन्य शर्मा ने कहा कि वह सत्ता लाभ के लिए नहीं, आम जनता की सेवा के लिए राजनीति में आये हैं। कहा कि वह युवाओं, महिलाओं की मांग को प्रमुखता से उठते रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वह तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए वोट करना उनका अपना मौलिक अधिकार है और अपने विवेक की आवाज सुनकर ही उन्होंने राज्यसभा के लिए वोट किया।

होशियार सिंह ने कहा कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। चाहे आर्थिक स्थिति हो या कानून व्यवस्था हो। हम निर्दलीय विधायक हैं और हमें राज्यसभा चुनाव में वोट देने का पूरा अधिकार था। पिछले 15 महीनों में विकास कार्य पूरी तरह से रुके पड़े हैं और इसलिए हमने खुद ही यह इस्तीफा देने और भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है।

इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि कांग्रेस की कार्यक्षमता चरमरा गई है। न तो हाईकमान का कोई प्रभाव है और न ही पार्टी कार्यकर्ताओं के लिये कोई सम्मान बचा है। विधानसभा क्षेत्र के हित में यह फैसला लिया।

निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि हमने राज्य और विधानसभा क्षेत्र के हित में यह फैसला लिया है। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में यह देश आगे बढ़ रहा है, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें भी यह मौका मिला है कि हम इसमें कुछ योगदान दें।

क्या देश के क़ानून से ऊपर हैं अरविंद केजरीवाल:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर बयान देते हुए कहा, 'अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसियों ने 9 बार समन भेजा पर वह जांच में शामिल नहीं हुए। क्या वे खुद को देश के कानून से ऊपर समझते हैं? वह करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं और रोज सदा सदाचार पर मीडिया में बाइट देते हैं। क्या वे अपने घर में बैठकर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और विजय नायर जैसे भ्रष्टाचारियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहेंगे? क्या अब देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जिनके खुद के कई नेता जेल में हैं और उन्हें बेल नहीं मिल रही, वे बताएंगे कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है? आखिर अरविंद केजरीवाल जांच से क्यों भाग रहे थे? गिरफ्तार न होकर वह कौन सा सच छुपाना चाह रहे थे?

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस द्वारा अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिए जाने के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'चोर चोर मौसेरे भाई हैं। देश की जनता को आज इनकी असलियत मालूम हो चुकी है। कांग्रेस और उसके बड़े नेता पहले सवाल खड़ा करते थे कि अरविंद केजरीवाल की जांच होनी चाहिए। लेकिन आज यह सभी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं।

अरविंद केजरीवाल के जेल से सरकार चलाये जाने के अटकलों के ऊपर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा की ये दिल्ली की जनता, कानून और लोकतंत्र का अपमान है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की बड़ी-बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि सोनिया गांधी के साथ दो दिन पूछताछ करने से पता लगेगा कि भ्रष्टाचार कैसे हुआ है। आज उन्होंने खुद 9 समनों की अनदेखी की।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि मनी ट्रेल मौजूद है। किसने किस से बात कराई, इसमें उपमुख्यमंत्री का क्या रोल था, यह सब है। इन सभी ने मिलकर यह बडा भ्रष्टाचार किया है और आज शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सभी नेता एक्सपोज़ हो चुके हैं। यह पहले कहते थे की राजनीति में नहीं आएंगे पर राजनीति में आये। कहते थे गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, लेकिन गाड़ी और बंगला लिया। कहते थे कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे पर कांग्रेस से भी हाथ मिलाया।

हिमाचल की 22 लाख महिलाओं को ठगने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार:योगी

शिमला/शैल। भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा की वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को 1500 रु नहीं मिलेगा, यह सरकार केवल मात्र हिमाचल की 22 लाख महिलाओं को ठगने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेताओं ने एक ब्लू फॉर्म भरवारा था और जो फॉर्म भरे गये थे उन महिलाओं को भी आज तक 1500 रु नहीं मिले।

वर्तमान समय में भी जो फार्म कांग्रेस सरकार भरवा रही है वह भी केवल मात्र एक छलावा है, 100% फॉर्म अमान्य करार होंगे क्योंकि परिवार में इन श्रेणियों के सदस्य होने पर महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ : परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनर, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक वर्ग के कर्मचारी होने पर महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सेवारत या भूतपूर्व सैनिक व सैनिक विधवा, मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील, मल्टी टास्क वर्कर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायतीराज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी, केंद्र-राज्य सरकार के तहत विभिन्न सार्वजनिक उपक्रम, बोर्ड, काउंसिल, एजेंसी में कार्यरत, पेंशनभोगी, वस्तु एवं सेवाकर के लिए पंजीकृत व्यक्ति तथा आयकरदाता के परिवार वाली महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। इससे साफ दिखता है कि यह सरकार महिलाओं को ठगने का कार्य कर रही है।

कांग्रेस सरकार के 15 महीने निराशाजनक रहे:रीना कश्यप

शिमला/शैल। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने कहा की कांग्रेस सरकार के 15 महीने निराशाजनक रहे हैं, इस सरकार ने

केवल मात्र जनता को ठगने का काम किया है। यह सरकार जनविरोधी, नीतिविरोधी, विकासविरोधी, कल्याणविरोधी है।

उन्होंने कहा की हिमाचल सरकार ने मार्च के महीने में ही दूसरी बार लोन लेने का फैसला किया है। इस वित्त वर्ष में लोन की आखिरी किस्त के तौर पर 672 करोड़ रुपये उठाये जा रहे हैं। इस वित्त वर्ष के लिए दी गई लोन लिमिट का 100 फीसदी इस्तेमाल करना पड़ा है। इस धनराशि को मिलाकर इस वित्त वर्ष में करीब 8072 करोड़ का लोन सरकार ने उठाया है। इससे पहले इसी महीने 1100 करोड़ का लोन लिया गया था। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 14000 करोड़ का लोन लिया है। अगर हिमाचल प्रदेश में कुप्रबंधन के लिए कोई सरकार जानी जाएगी तो वह केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार ही होगी।

उन्होंने कहा की कांग्रेस के अयोग्य छः और तीन निर्दलीय विधायकों के भाजपा में जाने के बाद राज्य सरकार ने राजनीतिक मामलों पर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। यह साफ दर्शाता है की कांग्रेस सरकार को अभी भी डर लग रहा है की उनके कोई विधायक पार्टी छोड़ न जाये। एक एक विधायक को सर्वेलेंस के अन्दर रखा गया है।

इस समिति अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होंगे। तीन मंत्रियों को सदस्य बनाया गया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी ने इसकी अधिसूचना जारी की है। यह मंत्रिमंडलीय उप समिति राज्य में राजनीतिक विषयों के अलावा आर्थिक मामलों को भी देखेगी। इसके सदस्य कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी होंगे। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को भी सूचित कर दिया गया है। शायद डैमेज कंट्रोल के लिए यह मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है।

अपना कुनबा संभालें भाजपा की चिंता छोड़े:डॉ.जनक राज

शिमला/शैल। भाजपा नेता एवं विधायक के डॉ. जनक राज ने कांग्रेस नेता ठाकुर रामलाल का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपना कुनबा संभालना चाहिए और भाजपा की चिंता है छोड़ देनी चाहिए, जहां कांग्रेस के नेता वोट दिखाकर भाजपा को डालते हैं और फिर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं और इतिहास में पहली बार ऐसा होता है जब निर्दलीय विधायक भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण करते हैं और इस्तीफा देते हैं आज से पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ।

यह सरकार निश्चित रूप से वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर पर ही रहेगी रामलाल ठाकुर जितना मर्जी प्रयास कर ले पर सरकार की स्थिति ठीक होना असंभव लग रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत डूबते हुए जहाज की तरह है और ऐसा लगता है कि यह जहाज जल्दी ही डूब जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनके नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं और स्वयं रामलाल ठाकुर खुद भी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। जिस संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो उससे संगठन की ताकत क्या रह गई होगी वह जग जाहिर है।

उन्होंने कहा कि इनके एक वरिष्ठ मंत्री गोमा जी प्रेस वार्ता कर रहे थे और उनके साथ बैठे नेता अपने संगठन के नेताओं के बारे में मलाईदार बातें कर रहे थे। इससे समझ आता है कि इन नेताओं कि अपने नेताओं के प्रति क्या मानसिकता है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.com

लोस उम्मीदवारों की घोषणा से भाजपा ने बनायी मनोवैज्ञानिक बढ़त

- सरकार की कर्ज लेने की गति से उपचुनावों में डबल इंजन की सरकार का नारा लगना तय
- हमीरपुर लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दाव पर
- अनुराग अब धूमल पुत्र से बढ़कर अनुराग सिंह ठाकुर हो गये हैं।

शिमला/शैल। प्रदेश भाजपा ने मण्डी और कांगड़ा लोकसभा सीटों के लिये भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मण्डी से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और कांगड़ा से डॉ. राजीव भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन दोनों उम्मीदवारों की घोषणा से प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के लिये भाजपा उम्मीदवारों के चयन का काम पूरा हो गया है। जबकि सरकार आक्रामकता के साथ मुकाबला

अनुराग सिंह ठाकुर(हमीरपुर)

सुरेश कश्यप(शिमला)

हुये चुनावों में देखने को मिला है। विधानसभा चुनावों में सोलन में कांग्रेस जितनी हावी रही थी उसके बाद उसी अनुपात में पीछे चली गयी है। शिमला में सरकार ने सबसे ज्यादा राजनीतिक पद बांटे हैं। इससे हर चुनाव क्षेत्र में इतने-इतने समानान्तर सत्ता केंद्र बन गये हैं जिनमें आपसी तालमेल की बजाये एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियां बन गयी हैं जिनका स्वभाविक लाभ भाजपा के पक्ष में जाता नजर आ रहा है।

हमीरपुर में भाजपा ने अनुराग को पांचवी बार टिकट दिया है। एक समय अनुराग की पहचान धूमल पुत्र होना थी। लेकिन आज अनुराग सिंह ठाकुर एक ऐसी स्वतंत्र पहचान बन गये हैं जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं। एक समय अनुराग को चंडीगढ़ शिफ्ट किये जाने की पूरी विसात बिछा दी गयी थी। अनुराग चंडीगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। यह मुख्य समाचार बना था। लेकिन इस विसात को मात देकर अनुराग ने प्रमाणित कर दिया कि

डॉ.राजीव भारद्वाज (कांगड़ा)

वह राष्ट्रीय स्तर पर गिने जा रहे हैं। आज हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से चार कांग्रेसी और दो निर्दलीय भाजपा में शामिल हो गये हैं। पांच विधानसभा उपचुनाव इसी लोकसभा क्षेत्र से होंगे। इसी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री आते हैं। इनके जिलों से विधायक क्रॉस वोटिंग करके भाजपा में भी शामिल हो गये और यह कुछ नही कर सके। लोकसभा चुनाव के लिये अपने आप ही कांग्रेस का पक्ष कमजोर कर लिया। क्या यह सब अनुराग की जानकारी और सहमति के बिना घट गया होगा? शायद नहीं। लेकिन इस सबमें अनुराग कहीं चर्चा तक में नहीं आये। ऐसे में आज अनुराग के सामने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री दोनों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। इस समय सुक्खू सरकार हर माह कर्ज के सहारे चल रही है और केंद्र सरकार पर यह आरोप है कि उसने कर्ज लेने की सीमा में कटौती कर दी है। क्या यह अपने में विरोधाभास नहीं हो

कंगना रनौत (मण्डी)

जाता? कठिन वित्तीय स्थिति के चलते सरकार गारंटीयां पूरी नहीं कर पा रही है न ही रोजगार दे पा रही है। क्या यह स्थिति स्वत: ही इस धारणा को न्योता नहीं दे रही है कि केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होनी चाहिये। यदि इन उपचुनावों में डबल इंजन कि सरकार का नारा लगता है तो क्या जनता उस पर विचार करने के लिये बाध्य नहीं हो जायेगी? इस परिदृश्य में क्या सुक्खू सरकार का संकट स्वत:ही गहरा नही होता जा रहा है।

नौ लोगों के भाजपा में शामिल

.....पृष्ठ 1 का शेष

है। पार्टी अध्यक्षा मण्डी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसा वह स्वयं का चुकी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के बैंक खाते सरकार ने सीज कर रखे हैं यह बात स्वयं मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्षा ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में रखी है। लेकिन इस वार्ता में यह स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ। और इसमें कानूनी तौर पर गलत क्या है। तथा पार्टी इसको आम आदमी के सामने रखकर उससे क्या अपेक्षा रखती हैं। यह विषय ही पत्रकार वार्ता में स्पष्ट न कर पाने से पार्टी की हताशा के खुलासे के साथ यह संदेश भी अनचाहे ही चला गया की चुनाव में खर्च का खुला प्रबंध पार्टी नही कर पायेगी और कार्यकर्ता तथा उम्मीदवार को बहुत कुछ अपने ही स्तर पर प्रबंध करना होगा। इस विषय पर कांग्रेस केंद्र सरकार और उसकी एजैन्सियों का कितना करेगी ऐसा कोई संदेश मुख्यमंत्री नहीं दे पाये हैं।

भाजपा ने इस चुनाव में बड़ी रणनीति के तहत कांगड़ा और मण्डी से नये चेहरों को उतारा है। जो पहली बार किसी चुनाव में आये हैं। ऐसे में इन लोगों के खिलाफ पहले से ही कुछ नहीं है। यह लोग प्रदेश भाजपा के किसी भी भीतरी समीकरण का कोई बड़ा पात्र अभी तक नहीं है न ही इनके खिलाफ़ सार्वजनिक जीवन से जुड़े कोई बड़े सवाल चर्चा में है। ऐसे में इन चेहरों के मुकाबले में कांग्रेस को यहां ऐसे ही उम्मीदवार उतारने होंगे जिनका राजनीतिक कद इनसे कहीं बड़ा हो और कांग्रेस के इस संकट में उनकी भूमिका एकदम पारदर्शी रही हो। भाजपा ने शिमला से सुरेश कश्यप को पुन: उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती दी है। कांग्रेस विधानसभा चुनावों में भाजपा पर शिमला लोकसभा क्षेत्र में बहुत भारी रही है। लेकिन सरकार बनने के बाद हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिये जाने के मामले में सरकार की कार्यप्रणाली जिस तरह से प्रश्नित रही है उससे सिरमौर में पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। सोलन नगर निगम में कांग्रेस की भूमिका के कारण ही नगर निगम कांग्रेस के हाथ से निकल गयी। इसका प्रभाव सोलन में ग्रामीण भूमि विकास बैंक और जोन्गिद्रा सहकारी बैंक के निदेशक मण्डल के लिये गया। इनके व्यवसायिक परिसरों पर छापेमारी की गयी। इनके समर्थकों को तंग करने की कारवाई शुरू हुई। लेकिन किसी भी कारवाई का कोई परिणाम सामने नहीं आ पाया। यहां तक बालूगंज की एफआईआर तक कारवाई गयी जिसमें यह लोग शामिल तक नहीं हुये। अन्त में मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से शिमला तक सड़क मार्ग से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ आये। इससे यह संदेश तो चला गया की मुख्यमंत्री के हाईकमान के साथ अच्छे रिश्ते है।

यह उम्मीद बनी थी कि कांग्रेस महासचिव प्रदेश की स्थिति का कोई कड़ा संज्ञान लेकर कुछ कदम अवश्य उठायेंगी। लेकिन व्यवहार में कुछ ऐसा नहीं हुआ। इससे यही संदेश गया कि अब भी हाईकमान प्रदेश को मुख्यमंत्री के चश्मे से देख रहा है। इससे मुख्यमंत्री को पार्टी और सरकार के डूबने तक बचाये रखने का संदेश तो गया लेकिन सरकार और संगठन को बचाने के प्रयासों का कोई संदेश नहीं गया। ऐसे में कार्यकर्ता अन्तत: किसके चेहरे पर चुनावों में उतरेगा? जिस नेतृत्व के कारण सरकार कुछ दिनों की मेहमान होने के कगार पर पहुंच चुकी हो उसका कार्यकर्ता कितने आत्मबल के साथ चुनाव में उत्तर पायेगा यह सवाल बड़ा होता जा रहा है। राजनीति में स्वार्थ सर्वोपरि हो जाता है यह एक स्थापित सत्य है और ऐसे में कांग्रेस के कुछ और लोग भी भाजपा में चले जायें तो कोई हैरानी नहीं होगी। क्योंकि सरकार बचाने के अभी भी कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। यह फैल चुका है की कुछ अधिकारी और राजनेता ईडी के रॉडार पर चल रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने के प्रयास किये हैं । ऐसे वातावरण में कोई सरकार कितने दिन सुरक्षित रह सकती है यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है । इस समय बागियों के खिलाफ जो कारवाई प्रशासनिक और पुलिस तंत्र के माध्यम से करने का प्रयास सरकार कर चुकी है अब उस सब को उसी भाषा में यह लोग लौटाने का प्रयास करेंगे यह स्वभाविक है। इसलिए आने वाले दिनों में व्यक्तिगत स्तर के आरोप लगाने का दौर शुरू होगा यह तय है।